नईदुनिया

खास-खबरें

महिलाओं के लिए विशेष गोल्ड लोन योजना

मुंबई। आईआईएफएल फाइनेंस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष गोल्ड लोन योजना शुरू की है। योजना के तहत महिलाओं को 0.81 प्रतिशत प्रति माह (9.72 प्रतिशत वार्षिक) से शुरू होने वाली ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। इसमें प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी और भारतीय रिजर्व बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर सोने के एवज में अधिकतम अनुमेय ऋण राशि उपलब्ध होगी। यह सुविधा देशभर में आईआईएफएल फाइनेंस की गोल्ड लोन शाखाओं पर मिलेगी। आईआईएफएल फाइनेंस के गोल्ड लोन प्रमुख मयंक शर्मा ने कहा कि घरों में रखा सोना महिलाओं की महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसे गोल्ड लोन के माध्यम से उत्पादक पूंजी में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि योजना में ऋण की लागत और आवेदन की लागत को कम करने पर जोर दिया गया है। आईआईएफएल फाइनेंस देशभर में गोल्ड लोन और एमएसएमई लोन सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है।

जीआई-टैग वाले 18 मीट्रिक टन मखाना की पहली खेप बिहार से ऑस्ट्रेलिया भेजी गई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: बिहार के जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना ने वैश्विक बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार के दरभंगा से पहली बार 18 मीट्रिक टन जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना की खेप समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इसे भारतीय कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने बिहार के बिहटा (बियाडा इंडस्ट्रियल एरिया) से ऑस्ट्रेलिया के लिए जीआई-टैग वाले 18 मीट्रिक टन मिथिला मखाना के पहले कमर्शियल समुद्री शिपमेंट ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किया है। मंत्रालय ने कहा कि दरभंगा जिले के मखाना उत्पादकों से लिए गए इस कंसाइनमेंट से बिहार के खास जीआई प्रोडक्ट की अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत होने और एक्सपोर्ट के जरिए किसानों के लिए कमाई के बेहतर मौके बनने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस खेप के लिए मखाना सीधे दरभंगा के किसानों से खरीदा गया है, जिससे उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18 फीसदी अधिक लाभ मिला है। इस पहल से न सिर्फ मिथिला मखाना की वैश्विक पहचान मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का नया रास्ता भी खुलेगा।

बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मखाना के इस एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पांच एमओयू पर हुए हस्ताक्षर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योग संगठनों और पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के साथ कई रणनीतिक समझौते किए हैं, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को वित्तीय, तकनीकी, निवेश और क्षमता निर्माण से जुड़ी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैशफ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वल्ट्र इंडिया, कार्स24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया (सीएसआई) के साथ समझौते किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के समर्थन को मजबूत करने के लिए कैशफ्री पेमेंट्स के साथ और उद्यमिता विकास और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए डार्विन डायनेमिक्स एलएलपी के साथ साझेदारी की गई है। इसी तरह डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन को मजबूत करने के लिए वल्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एआई संचालित मोबिलिटी इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कार्स24 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किए हैं, जबकि डीपीआईआईटी ने भारतीय स्टार्टअप की वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने के लिए काउंसिल फॉर स्टार्टअप इंडिया के साथ गठजोड़ किया है।

फेसबुक-इंस्टाग्राम की कानूनी सुरक्षा पर संकट, सरकार ने मेटा से मांगा जवाब

रिकमेंडेशन सिस्टम और कंटेंट प्रमोशन पर घिरी मेटा, सेफ हार्बर वापस लेने की चेतावनी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोशल मीडिया कंपनी मेटा और भारत सरकार के बीच हुई बैठकों के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम की कानूनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मुख्य मुद्दा यह है कि मेटा का रिकमेंडेशन सिस्टम और पैसों के बदले कंटेंट प्रमोशन उसे सामान्य प्लेटफॉर्म की श्रेणी में रखता है या पब्लिशर की भूमिका में।

अगर कोई प्लेटफॉर्म अपने स्तर पर यह तय करता है कि किस यूजर को कौन सा कंटेंट दिखाया जाए और पैसे लेकर किसी कंटेंट को प्रमोट करता है, तो उसे पब्लिशर माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी को प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होने वाले कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है और आईटी एक्ट के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर स्टेटस भी खत्म हो सकता है।

आईटी एक्ट की धारा 79 सोशल मीडिया कंपनियों को सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा देती है। इसके तहत किसी यूजर द्वारा पोस्ट की गई विवादित या गलत जानकारी के लिए प्लेटफॉर्म को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। हालांकि, यह छूट तभी लागू रहती है, जब कंपनी ड्यू डिलिजेंस यानी कानूनी नियमों और जरूरी सावधानियों का पालन करे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यदि प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम के जरिए यह तय करता है कि कौन सा कंटेंट किस यूजर को दिखाया जाए, तो यह पब्लिशिंग के दायरे में आ सकता है। नियमों का पालन नहीं होने पर आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत कंपनी पर सीधी कार्रवाई की जा सकती है।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट को अस्थायी रूप से हटाने या रिस्ट्रिक्ट करने के बाद सरकार ने मेटा के ग्लोबल अफेयर्स हेड जोएल कपलान को समन भेजा था। इसके बाद उनकी टीम ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की।

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री की पोस्ट हटने और प्लेटफॉर्म पर डीपफेक समेत अन्य गड़बड़ियों को लेकर मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग की ओर से माफी मांगी गई। संसदीय स्थायी समिति ने भी इस मामले पर नाराजगी जताते हुए जुकरबर्ग से तीन दिन में माफी मांगने को कहा था।

बैठक में सरकार ने एआई-जनरेटेड हानिकारक कंटेंट और डीपफेक वीडियो को लेकर भी सवाल उठाए। मेटा से पूछा गया कि रिपोर्ट किए जाने के बाद भी ऐसे कंटेंट बार-बार क्यों दिखाई देते हैं। सरकार ने भारतीय भाषाओं और स्थानीय परिस्थितियों को समझने वाली टीमों के साथ कंटेंट मॉडरेशन में ह्यूमन ओवरसाइट बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

सात सीटर कारों में अर्टिगा का दबदबा जुलाई में 19 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं

जुलाई में 19,444 यूनिट की बिक्री, एमपीवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी की कार की करीब 49 प्रतिशत हिस्सेदारी

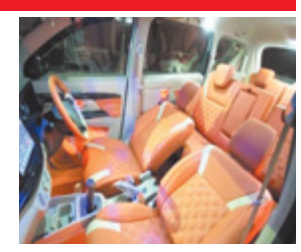

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सात सीट वाली फैमिली कार खरीदने वालों के बीच एमपीवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा का दबदबा कायम है। जुलाई 2026 में अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी रही। कंपनी ने इस महीने इसकी 19,444 यूनिट बेचीं। एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा की हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत रही। यानी इस श्रेणी में बिकने वाली लगभग हर दो कारों में से एक अर्टिगा रही।

सात सीट वाली फैमिली कार खरीदने वालों के सामने आमतौर पर एमपीवी और एसयूवी का विकल्प रहता है। एमपीवी में ज्यादा केबिन स्पेस और व्यावहारिकता के कारण अर्टिगा लंबे समय से ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। जुलाई की बिक्री में अर्टिगा के बाद टोयोटा रूमियन दूसरे स्थान पर रही। इसकी 4,724 यूनिट बिकीं। इसके बाद किआ कैरेंस क्लैविस की 3,529 यूनिट और किआ कैरेंस की 1,612 यूनिट की बिक्री हुई। रेनो ट्राइबर 1,242 यूनिट की बिक्री के साथ पांचवें स्थान पर रही। आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में एमपीवी सेगमेंट की कुल बिक्री 39,631 यूनिट रही। इनमें अर्टिगा की 19,444 यूनिट की बिक्री के साथ करीब आधी हिस्सेदारी रही। इसके बाद रूमियन की हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत और कैरेंस क्लैविस की करीब 9 प्रतिशत रही। मारुति सुजुकी अर्टिगा की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण इसकी कीमत, सात सीटों की क्षमता और उपयोगिता मानी जाती है। फैमिली कार के तौर पर इसे शहर और लंबी दूरी दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है। जुलाई के बिक्री आंकड़ों में एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा की बढ़त बाकी मॉडलों से काफी अधिक रही।

गूगल मैप्स हुआ और स्मार्ट, होटल से खाना ऑर्डर करने तक मिलेंगी सुविधाएं

'आस्क मैप्स' में जेमिनी एआई का सपोर्ट, हिंदी में सवाल पूछकर होटल, रेस्टोरेंट और यात्रा से जुड़ी जानकारी ले सकेंगे यूजर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: गूगल मैप्स में कई नए फीचर जोड़े गए हैं, जिससे यह केवल रास्ता बताने वाला एप नहीं रहेगा। गूगल ने अपने एआई फीचर 'आस्क मैप्स' को जेमिनी एआई की मदद से अधिक स्मार्ट बनाया है। अब यूजर इसके जरिए रेस्टोरेंट खोजने, खाना ऑर्डर करने, होटल ढूंढने और यात्रा की योजना बनाने जैसे काम कर सकेंगे। ये नए फीचर भारत में भी उपलब्ध होंगे और आस्क मैप्स में हिंदी भाषा का समर्थन भी मिलेगा।

आस्क मैप्स यूजर की जरूरत के अनुसार विकल्प सुझाएगा। उदाहरण के लिए, रास्ते में जल्दी खाना मिलने वाले और शाकाहारी विकल्प वाले रेस्टोरेंट की जानकारी मांगी जा सकती है। इसके बाद एआई यूजर की पसंद के अनुसार विकल्प चुनेगा और जरूरत पड़ने पर खाना ऑर्डर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकेगा। फिलहाल इसके लिए स्क्वायर और टोस्ट जैसे साझेदार मंचों का समर्थन मिलेगा। आगे उबर ईट्स का समर्थन भी आने वाला है। भुगतान यूजर को स्वयं करना होगा।

होटल खोजने के लिए भी यूजर अपनी जरूरत के अनुसार शर्तें बता सकेंगे। जैसे हवाईअड्डे के पास कम कीमत वाला होटल, जिसमें जिम की सुविधा हो और आसपास अच्छे रेस्टोरेंट हों। आस्क मैप्स इन शर्तों के आधार पर होटल के विकल्प देगा। इसके बाद होटल की वेबसाइट या बुकिंग साझेदार के माध्यम से कमरा बुक किया जा सकेगा।

नए फीचर में व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर सुझाव देने की सुविधा भी है। अनुमति देने पर आस्क मैप्स जीमेल और आगे चलकर गूगल कैलेंडर की जानकारी का इस्तेमाल कर सकेगा। यात्रा, होटल बुकिंग या किसी कार्यक्रम से जुड़े ईमेल के आधार पर यह रास्ते, घूमने की जगह और खाने के विकल्प सुझा सकेगा। यह सुविधा वैकल्पिक होगी और डिफॉल्ट रूप से बंद रहेगी। आस्क मैप्स पिछली बातचीत को भी याद रख सकेगा। वहीं से यात्रा की योजना आगे बढ़ाई जा सकेगी। सार्वजनिक परिवहन के लिए बस, ट्रेन, मेट्रो और फेरी की लाइव जानकारी भी मिलेगी। देरी या मार्ग में बदलाव की सूचना भी एप पर दिखाई जाएगी। भारत में आस्क मैप्स को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है।

सोना 1.49 लाख और चांदी 2.31 लाख पर पहुंची, पांच दिन में जोरदार तेजी

पांच दिन में सोना 7,064 और चांदी 14,094 महँगी, खरीददारी कमजोर

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सोने-चांदी की कीमतों में इस सप्ताह जोरदार तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, पांच कारोबारी दिनों में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 7,064 बढ़कर 1.49 लाख पर पहुंच गई। वहीं, एक किलोग्राम चांदी के भाव में 14,094 की बढ़ोतरी हुई और कीमत 2.31 लाख हो गई।

सप्ताह की शुरुआत सोमवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 1.42 लाख और एक किलोग्राम चांदी की कीमत 2.17 लाख थी। शुक्रवार को सोने के भाव में 1,181 और चांदी में 5,707 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे एक दिन पहले गुरुवार को सोना 1.48 लाख और चांदी 2.25 लाख पर थी।

तेजी के प्रमुख कारण

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध जैसे हालात प्रमुख कारण हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने और चांदी की ओर बढ़ा है। मेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के संकेत और नरम रुख से भी कीमती धातुओं को समर्थन मिला है। वहीं, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के कारण अन्य मुद्राओं वाले खरीदारों के लिए सोने-चांदी में निवेश अधिक आकर्षक हुआ है। दुनिया के केंद्रीय बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। इससे सोने की मांग मजबूत बनी हुई है। चांदी को सौर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों से मिलने वाली औद्योगिक मांग का भी फायदा मिल रहा है।

इस साल भी सोने में तेजी

2026 में अब तक सोना करीब 16 हजार महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोने की कीमत 1.33 लाख से अधिक थी, जो अब 1.49 लाख हो गई है। चांदी इस साल करीब 1 हजार महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को इसकी कीमत 2.30 लाख प्रति किलोग्राम थी। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख और चांदी ने 3.86 लाख का सर्वकालिक उच्च स्तर बनाया था।

कमोडिटी विशेषज्ञ अजय केडिया के अनुसार, साल के अंत तक सोना 1.60 लाख और चांदी 2.80 लाख तक पहुंच सकती है। उनका कहना है कि निवेशकों को एकमुश्त निवेश से बचना चाहिए।

सोने और चांदी में ईटीएफ के जरिए भी निवेश किया जा सकता है। गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ की खरीद-बिक्री बीएसई और एनएसई पर शेयरों की तरह की जा सकती है। इसमें भौतिक सोना या चांदी नहीं मिलता, बल्कि कीमत के अनुरूप राशि प्राप्त होती है। ईटीएफ में 500 रुपये से कम राशि से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। इसके लिए ब्रोकर के माध्यम से डीमैट खाता खोलना होता है।

फॉक्सवैगन वर्टस का एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, सिर्फ 150 यूनिट उपलब्ध

जीटी प्लस स्पोर्ट ट्रिम पर आधारित लिमिटेड एडिशन में 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग समेत कई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: फॉक्सवैगन ने अपनी प्रीमियम सेडान वर्टस का एनिवर्सरी एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। कंपनी ने इस कार को चार साल पहले भारत में पेश किया था। नया एनिवर्सरी एडिशन वर्टस के जीटी प्लस स्पोर्ट ट्रिम पर आधारित है। इसकी कीमत 19.20 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। कंपनी इस लिमिटेड एडिशन की सिर्फ 150 यूनिट उपलब्ध कराएगी। फीचर्स बढ़ाए जाने के बावजूद इसकी कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वर्टस एनिवर्सरी एडिशन में खास अवाकाडो पर्ल एक्सटीरियर रंग दिया गया है। इसके साथ ब्लैक रूफ, ब्लैक अलॉय व्हील्स, रेड कैलिपर्स और ब्लैक बूट-लिप स्पॉयलर मिलते हैं। कार में ग्लॉस ब्लैक फ्रंट बंपर, डार्केंड हेडलैंप और टेललैंप के साथ ऑल-ब्लैक कैबिन दिया गया है। डैशबोर्ड पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश इंसर्ट भी मिलता है। कार में पडल लैंप्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसे अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा लेदर अपहोल्स्ट्री, रेड एंबिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड सनरूफ, 10 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम और पैडल शिफ्टर मिलता है। सुरक्षा के लिए कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। वर्टस एनिवर्सरी एडिशन में 1.5 लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 150 हॉर्सपावर की अधिकतम पावर और 250 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। इसके साथ 7-स्पीड डीएसजी डुअल-क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है। कंपनी के अनुसार कार 19.62 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

नौकरी हो या फ्रीलांस काम, इमरजेंसी फंड जरूरी; जानें 3-6-9 नियम से कितना बचाएं

इमरजेंसी फंड के लिए अपनाएँ 3-6-9 नियम, 3 से 12 महीने का खर्च रखें अलग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी, कार खराब होने या नौकरी जाने जैसी परिस्थितियों में रोजमर्रा की जरूरतों और मौजूदा सेविंग्स पर असर न पड़े, इसके लिए इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सही फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड को अलग रखना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर मुख्य सेविंग्स को इस्तेमाल न करना पड़े। टैक्स और फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म क्लियरटैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैलरीड क्लास और अनियमित आय वाले फ्रीलांसर्स 3-6-9 नियम के जरिए अपने लिए इमरजेंसी फंड का लक्ष्य तय कर सकते हैं। यह नियम व्यक्ति की लाइफस्टाइल, आय की स्थिरता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर जरूरी रकम निर्धारित करने में मदद करता है।

3-6-9 नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सिंगल है और उसकी आय पूरी तरह स्थिर है, तो उसे कम से कम तीन महीने के जरूरी खर्च के बराबर रकम इमरजेंसी फंड में रखनी चाहिए। अगर आय स्थिर है, लेकिन परिवार के सदस्य उस पर निर्भर हैं, तो छह महीने के खर्च का फंड रखना उचित है।

वहीं, सिंगल व्यक्ति की आय अनिश्चित या अनियमित है, जैसे फ्रीलांस या प्रोजेक्ट आधारित काम, तो उसे नौ महीने के खर्च के बराबर फंड रखना चाहिए। अगर आय अनियमित होने के साथ परिवार की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति पर है, तो 12 महीने के खर्च का फंड तैयार करने की सलाह दी जाती है। परिवार में गंभीर बीमारी या लोन की ईएमआई होने पर फंड का आकार और बड़ा रखा जा सकता है।

मान लीजिए किसी व्यक्ति का जरूरी मासिक खर्च 25,000 है। ऐसे में तीन महीने के लिए 75,000, छह महीने के लिए 1.50 लाख, नौ महीने के लिए 2.25 लाख और 12 महीने के लिए 3 लाख की जरूरत होगी। एक बार में बड़ी रकम जमा करना मुश्किल हो तो छोटे लक्ष्य से शुरुआत की जा सकती है। पहले तीन महीने के खर्च का लक्ष्य बनाकर हर महीने 500 से 1,000 या क्षमता के अनुसार बचत शुरू की जा सकती है।

स्पेशल खबर होर्मुज संकट के बाद बदली ऊर्जा आपूर्ति रणनीति, मई-जुलाई में भारत ने 7.08 मिलियन टन एलएनजी आयात की

महँगी एलएनजी से भारत पर 3,360 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: मध्य-पूर्व संकट और होर्मुज स्ट्रैट में आपूर्ति प्रभावित होने के बाद भारत की ऊर्जा आपूर्ति रणनीति में बदलाव आया है। इक्विरस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, कतर को पीछे छोड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) सप्लायर बन गया है। मई से जुलाई 2026 के दौरान कतर से भारत का एलएनजी आयात 91 प्रतिशत घटा, जबकि अमेरिका से आपूर्ति 253 प्रतिशत बढ़ी।

कतर की सस्ती गैस की आपूर्ति घटने और अमेरिका सहित अन्य देशों से महंगी गैस खरीदने के कारण भारत को करीब ?3,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। मार्च-अप्रैल में कतर की आपूर्ति बाधित होने पर भारत ने अमेरिका से जुड़े और स्पॉट कार्गो के जरिये एलएनजी की भरपाई की। केप्लर के अनुसार, अमेरिकी एलएनजी कार्गो कतर की तुलना में करीब 2-3 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू महंगे थे। इससे भारत की औसत एलएनजी खरीद कीमत 499 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 602 डॉलर प्रति टन हो गई। आयात मात्रा 22.9 प्रतिशत घटने के बावजूद करीब 353 मिलियन डॉलर यानी ?3,360 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

मई-जुलाई के दौरान भारत ने कुल 7.08 मिलियन टन एलएनजी आयात की, जो पिछले साल की समान अवधि से 15 प्रतिशत अधिक है। अमेरिका ने 2.19 मिलियन टन की आपूर्ति की। नाइजीरिया 1.31 मिलियन टन के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ओमान से आपूर्ति में 341 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि कतर से आयात घटकर 0.23 मिलियन टन रह गया। होर्मुज संकट के बाद भारत की एलपीजी आपूर्ति में भी अमेरिका की भूमिका बढ़ी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारत की जरूरत की करीब 67 प्रतिशत एलपीजी अब अमेरिका से आ रही है। उन्होंने बताया कि संकट के बावजूद देश में एलपीजी और कच्चे तेल की कमी नहीं होने दी गई। भारत ने कच्चे तेल के आपूर्ति स्रोत 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिए हैं और करीब 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार बनाए रखा।

जून में भारत की कुल प्राकृतिक गैस मांग बढ़कर 197 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन रही। एलएनजी की खपत 110 एमएमएससीएम और घरेलू गैस की खपत 87 एमएमएससीएम रही। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 58 एमएमएससीएम के साथ सबसे बड़ा ग्राहक रहा।

वैश्विक स्तर पर एशियाई स्पॉट एलएनजी कीमतें 20 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से ऊपर बनी हुई हैं। सरकार ने दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए ?84,000 करोड़ के समुद्र मंथन कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। इसके तहत गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को बढ़ावा दिया जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका के एक इलाके में ही उगता है रूइबोस, दुनिया में बढ़ रही मांग

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के सेडरबर्ग पहाड़ों में उगने वाला रूइबोस पौधा इन दिनों दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहा है। इसकी पत्तियों से बनने वाली रूइबोस चाय कैफीन रहित होती है और अब 50 से ज्यादा देशों में इसकी खपत हो रही है। वर्ष 2022 से 2024 के बीच रूइबोस की खपत में 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वहीं, 2025 में इसका निर्यात पहली बार 10 हजार टन से अधिक पहुंच गया। रूइबोस का अर्थ लाल झाड़ी होता है। यह पौधा दक्षिण अफ्रीका के करीब 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही प्राकृतिक रूप से उगता है। इसके लिए खास मिट्टी, कम बारिश और सूखा मौसम जरूरी होता है। सेडरबर्ग क्षेत्र में ये परिस्थितियां मौजूद हैं। यही वजह है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में इसकी खेती आसानी से नहीं हो पाती। इसे स्थानिक पौधा माना जाता है, यानी ऐसा पौधा जो प्राकृतिक रूप से किसी एक खास क्षेत्र में ही पाया जाता है।

रूइबोस की खासियत यह है कि इसमें कैफीन नहीं होता। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल जैसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। शुरुआती शोध में इन तत्वों को शरीर के लिए उपयोगी माना गया है। हालांकि, इसके स्वास्थ्य लाभों को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी और शोध की जरूरत है।

रूइबोस का इस्तेमाल अब केवल चाय तक सीमित नहीं है। इससे हर्बल ड्रिंक, त्वचा की देखभाल से जुड़े उत्पाद और अन्य वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं।